

सोवियत विघटन के पश्चात् रूस की संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या

डा० विपिन कुमार नीरज

एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पीलीभीत

Article Info

Volume 6, Issue 2

Page Number : 952-956

Publication Issue

March-April-2019

Article History

Accepted : 05 March 2019

Published : 20 March 2019

सारांश— पूर्वी एवं मध्य यूरोप की अर्थव्यवस्थाएँ संक्रमण काल से गुजर रही थी। इस अवस्था में बेरोजगारी की समस्या पर विश्लेषण करना अत्यन्त दुष्कर था। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण या माडल नहीं था, जबकि केन्द्रीय रूप से प्रायोजित अर्थव्यवस्था एक बाजार अर्थव्यवस्था में बदली हो, और न ही कोई आर्थिक सिद्धांत इस परिवर्तन के बारे में उपलब्ध था जिसको कि आधार मान सके। एक विशेष प्रकार की कठिनाई तब और सामने आती है, जब हम पाते हैं कि परिवर्तन किसी क्षेत्र विशेष में न होकर व्यापक स्तर पर और द्रुत गति से हो रहा हो। मुद्रा बाजार उपभोक्ता वस्तुओं व्यापार उत्पाद आदि में एक साथ और तेजी से बदलाव हो रहे थे। इसलिए किसी एक क्षेत्र उदाहरणार्थ श्रम बाजार का विश्लेषण करते समय हमें अर्थ व्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में हो रहे बदलाव को देखना होता है वरना श्रम बाजार पर टिप्पणी करते समय अर्थव्यवस्था के कमोवेश स्थिर होने का श्रम हो सकता था वर्तमान संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पर विचार करने से पूर्ण यह समझ लेना आवश्यक होगा कि केन्द्रीय से प्रायोजित अर्थ व्यवस्था में इस क्षेत्र की क्या स्थिति थी।

सोवियत संघ में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित अर्थव्यवस्था में लोगों को पूर्णरूप से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त थी। प्रत्येक कर्मचारी तथा कृषक को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल किया गया था। सोवियत रूस में बेरोजगारी भूत्ता नाम की कोई बीमा योजना नहीं थी। क्योंकि लोगों को पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त था। लोगों के आर्थिक सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी हितों का राज्य संरक्षण करता था। वृद्धावस्था में पेंशन एवं मृत्यु के बाद आश्रितों को आर्थिक सहायता राज्य बजट से प्राप्त होती थी।

वेतन अथवा श्रम पर काम करने वाले पुरुषों को 25 वर्ष वृत्ति तथा 60 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने पर पेंशन प्राप्त होती थी स्त्रियों के लिए यह शर्त 20 एवं 55 वर्ष थी।

महिलाओं को प्राप्त विशेष हितों में प्रसूति एवं वैवाहिक अनुदान मुख्य थे। उन महिलाओं को जिन्होंने 3 मास किसी व्यवसाय में कार्य किया था, अवकाश की सम्पूर्ण सुविधाएँ प्राप्त होती थी। सन्तान उत्पन्न होने पर एक विशेष अनुदान दिया जाता था। विकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था थी। बच्चों के लिए शिशु गृहों की भी व्यवस्था थी।

सोवियत संघ के आर्थिक एवं औद्योगिक जीवन में ट्रेड यूनियन संगठन का अति महत्वपूर्ण स्थान था। वे श्रमिकों के पारिश्रमिक निर्धारण एवं नियोजन में भाग लेते थे। कृषि के क्षेत्र में सामूहिक फर्म थी जिसको अधिक स्वायत्ता प्राप्त थी।

एक तरफ जहाँ इन सब अच्छाइयों एवं मानवीय जीवन के उत्कृष्ट पहलू को लेकर इसकी तारीफ की जाती रही वहीं दूसरी तरफ इसकी जबर्दस्त आलोचना भी की जाती रही। इन आलोचनाओं की सच्चाई का निहितार्थ हमें सोवियत संघ के विघटन के रूप में

देखने को मिला। सोवियत रूस की प्रगति सदा से ही एक विवादास्पद विषय रहा था पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने सोवियत रूस दारा विकास के प्रकाशित आँकड़ों को भ्रामक बताया था। दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था न होने से लाभ-हानि के प्रति लोग ज्यादा सचेत नहीं थे। लोगों ने ज्यादा संरक्षण का दुरुपयोग भी किया।

इन पृष्ठभूमियों के आलोक में हम देखते हैं। संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या किस तरह उभर कर सामने आई।

पोलैण्ड में 1989 से शुरू हुआ सुधारों का दौर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ सभी संक्रमण कालीन अर्थव्यवस्थाओं में लगातार घटता उत्पादन मुद्रा स्फीति की बढ़ती दर, कमजोर राजनीतिक नेतृत्व गोर्वाच्योव की ग्लासनोस्त एवं पेरोस्ट्रोइका के रूप में पूँजीवाद के नींव की स्थापना ने मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त किया। पूँजीवाद का मूल स्वरूप ही सामूहिक हित व अहित देखने के बजाय लाभ-हानि को ज्यादा महत्व देता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में भी सुधारों का दौर शुरू हुआ। सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंप दिया गया। परिणामतः लोगों की छँटनी शुरू की गयी। रोजगार के जो नये क्षेत्र सृजित हो रहे थे उसमें रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या की अपेक्षा बेरोजगार होती संख्या अधिक थी।

उदारीकरण, वैश्वीकरण, बाजारीकृत अर्थ-व्यवस्था ने बेरोजगारी के स्तर को बढ़ाया। बेरोजगारी की समस्या का सम्बन्ध उत्पादन में गिरावट का होना नये क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलने की अपेक्षा छँटनी अधिक होना था। संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था को देखे जो प्रारम्भिक वर्षों 90 से 93 तक उत्पादन लगातार गिरा। दस प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से गिरावट आई थी। केवल पोलैण्ड एवं स्लोवानिया ही इसके अपवाद रहे जिनकी गिरावट दस प्रतिशत से कम रही। रूस में 1992 में मुद्रा स्फीति की दर दो हजार प्रतिशत से भी ज्यादा हो गयी थी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 25 गिरावट आई। उपभोग वस्तुओं की कीमतों में 5 से 10 गुना अधिक की वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा भण्डार में कमी आई। रुबल का अवमूल्यन किया गया।

रूस की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट आती रही। देश में बेरोजगारों की तादाद तेजी से बढ़ी अनेक घाटे में चल रहे कारखाने बन्द कर दिये गये। येल्टसिन के विदेश मंत्री गैदर ने 92 के अंत तक बेरोजगारों की संख्या 60 लाख हो जाने की बात की थी परन्तु यह संख्या उससे कहीं अधिक थी। 1994 तक बेरोजगारी तीव्र गाति से बढ़ी। सभी संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था वाले देशों में यह दहाई अंक में पहुँच गयी थी अपवाद

केवल चेक एवं रूस ही थे, क्योंकि यहाँ उदारीकरण की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही थी। उत्पादन में बहुत ज्यादा गिरावट एवं घाटे को देखते हुए खुली बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी होना कम जान पड़ता था। विशेष रूप से ऐसे समय में जब सफल पुनर्स्थापना के लिए त्वरित विकास जल्दी हो। कुछ लोगों की राय थी कि लोगों के समय को कम करके रोजगार में रखने की अपेक्षा रोजगार को कम किया जाय। ज्यादातर देशों में रोजगार में कमी अधिकारिक तौर पर बेरोजगारी की बढ़ने की दर से अधिक थी। यह श्रम जमघट अपेक्षाकृत धीमी पुनर्संरचना के कारण बताया जाता था, घाटे में चल रह उद्योग अभी भी पूरी तरह से बन्द नहीं हो रहे थे। इसके लिए सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोगों को काम देने के नाम पर रोजगार की संख्या नहीं बल्कि कार्य करने के घण्टों में कमी की गयी थी। पिछली केन्द्रीय स्तर पर संचालित अर्थव्यवस्थाओं में उद्यमदर, पश्चिम की तुलना में बहुत अधिक थी। इन अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार, सामाजिक स्थिरता एवं सुरक्षा का एक माध्यम था।

पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में असुरक्षा एवं असमानता के खिलाफ सामाजिक बराबरी व सुरक्षा को कर व हस्तान्तरण वितरण के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, वहीं सामाजिक अर्थव्यवस्थाओं में यह भूमिका सरकारी उद्योगों द्वारा निभाई जाती है। रोजगार सुनिश्चित होता था परन्तु वेतन कम था। सबको जीविका का आधार मिला हुआ था। रोजगार का अर्थ था कि लोगों को पेंशन बिमारी भत्ता और परिवार भत्ता प्राप्त होता था। इन सब कारणों से इन व्यवस्थाओं में ऊँचे स्तर पर सहभागिता दर तय थी विशेष रूप से बुढ़े व महिलाओं के सन्दर्भ में। इसलिए सहभागिता दर में आने वाली गिरावट को उद्योगों भत्तों व लाभ के संबंध में उद्योगों की बदली हुई भूमिका को बदली हुई भूमिका को काफी हद तक जिम्मेदार ठहरा सकते हैं।

सहभागिता दर में कमी आने का एक और भी महत्वपूर्ण कारण यह था कि कुछ देशों में बेरोजगारी भत्ता का बहुत कम या बिल्कुल न होना लोगों को बेरोजगार के रूप में पंजीकृत कराने से हतोत्साहित करता था। ढेर सारे अपंजीकृत लोग काली अर्थव्यवस्था से भी जुड़ जाते थे। रूस के सन्दर्भ में यह स्थिति विशेष रूप से सही थी। जब बहुत से लोग मजदूरी के नाम पर कुछ भी नहीं पाते हो उदाहरणार्थ रूस के कई क्षेत्रों के कर्मचारियों को कई महीनों तक तनख्याह ही नहीं मिली। ऐसी दशा में रोजगारी एवं बेरोजगारी का अन्तर साफ नजर नहीं आता। त्पस्थ की अक्टूबर 1998 के रिपोर्ट में रूस में 13.3: बेरोजगारी बतायी गयी थी जो कि अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन और आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के बेरोजगारी की परिभाषा के अनुसार मापा गया था। यह राष्ट्रीय ऑँकड़ा क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ढक देता है जहाँ इंगुस्तिया में 51: बेरोजगारी थी वहीं मास्कों शहर में न्यूनतम 5: बेरोजगारी थी। 1991 में बेरोजगारी भत्ते की सुविधा प्रदान की गई थी। बेरोजगारी भत्तों नौकरी के समाप्त होने के पहले के औसत मजदूरी के हिसाब से दिया जाता था जो सिद्धातः पहले छः महीने में काफी होता था और यह बेरोजगारों को एक वर्ष तक मिलता था। इसका अर्थ यह हुआ कि कम समय की बेरोजगारी गरीबी के लिए बड़ा कारण नहीं बन सकती। लेकिन सर्वे के सारे ऑँकड़े दिखाते थे कि बेरोजगारी घरों में गरीबी को बढ़ावा देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थी। सुधार के प्रारम्भिक वर्षों में प्रशासनिक रुकावटों और बेरोजगारी को बुरा मानने के कारण बेरोजगारी भत्ता लेने वाली की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। मुद्रास्फीति की बढ़ती दर ने भत्ता का वास्तविक लाभ कम कर दिया था। बेरोजगारी को अब एक काला धब्बा नहीं माना जा रहा था। मुद्रास्फीति पर भी कुछ हद तक काबू पा लिया गया था। फिर भी रोजगार संचयनिधि का कम होना व उसका क्षेत्रीय बंटवारा ठीक से न हो पाना परिस्थिति को और खराब कर रहा था। इसका अर्थ यह था कि जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेरोजगार थे वहाँ रोजगार संचय निधि को दी जाने वाली सहयोग राशि—सबसे कम थी। फलस्वरूप यदि रोजगार संचय निधि के पास भत्ता देने के लिए पैसा नहीं था तो नहीं दिया जाता या न्यूनतम मजदूरी के दर पर या वस्तु रूप में दिया जाता था। इन कारणों से कम ही बेरोजगार अपने को पंजीकृत कराते था केवल दो—तिहाई पंजीकृत बेरोजगार ही वास्तव में भत्ते के हकदार होते थे। उनमें से बहुत कम को भत्ता मिल पाता था। 1996 में पंजीकरण के नियमों में बदलाव आने के कारण पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में लगातार गिरावट आई थी। अप्रैल 1996 में जहाँ 27.7 लाख लोग पंजीकृत थे वहीं सितम्बर 1998 में इनकी संख्या घटकर 17.5 लाख हो गयी। यह स्थिति तब थी जबकि रोजगार कम हो रहा था। बेरोजगारी भत्ता पाने वाले पंजीकृत बेरोजगारों का अनुपाल 1996 में 68: से घटकर 59: हो गया। दीर्घकालीन बेरोजगारों का समय ज्यादा हो जाने के कारण भत्ता के लिए अर्हता समाप्त हो गयी और 1996 के अन्त तक करीब 7.5 लाख लोग जो भत्ता पाने के हकदार थे उनको भत्ता मिला ही नहीं। कुछ क्षेत्रों के लोगों को चार से छः महीने बाद मिला। बहुतों को वस्तु रूप में मिला। 1997 में स्थिति और बुरी हो गयी क्योंकि विभिन्न उद्योगों ने रोजगार संचयनिधि को पैसा देना लगभग बन्द कर दिया। इस प्रकार रोजगार सेवा अधिकारों के अनुसार भत्ता मिलने में एक साल की देर होने लगी। बाद में किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जा रहा था।

लेबर फोर्स सर्वे ने बेरोजगारों की जो संख्या बतायी थी उसके अलावा भी श्रमवल भागीदारी में भारी गिरावट आई थी। इस सर्वेक्षण में केवल उन बेरोजगारों को गिना था जो बिना किसी आय के होने के साथ—साथ सक्रिय रूप से काम ढूँढ़ रहे थे। रोजगार के अवसर मिलने पर वे उपलब्ध हो सकते थे। किन्तु 1992 से 1998 के बीच वो एक करोड़ लोग भी रूस में थे जो श्रम बल से बाहर हो गये। औरतों के बारे में जो शुरू से ही धारणा थी कि इनकी संख्या काफी घटेगी परन्तु स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज्यादा मात्रा में बाहर हुए। श्रम बल भागीदारी में सबसे ज्यादा कमी 15 से 19 वर्ष के समूह में आई थी। जिनकी भागीदारी 2/3 कम हुई थी। 55 से 60 उम्र वाले पुरुष व 50 से 55 उम्र वाली महिलाओं की संख्या में भी कमी आई थी। किशोरों और युवाओं की भागीदारी में कमी आने का अर्थ यह नहीं था कि व बड़े स्तर पर शिक्षा की ओर उन्मुख हो गये थे। यद्यपि विद्यालयों में नाम लिखाने वालों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई थी लेकिन अधिकतर शहरी किशोर अपने माता—पिता पर बोझ बने रहने और लोगों को बेबूफ बनाकर जीवन जीने में अधिक आनन्द ले रहे थे बशर्ते इसके कि नौकरी की तलाश करें। 15 से 19 वर्ष की आयु के किशोरों में से 30: स्वरोजगार करते थे। 20 वर्ष से 24 वर्ष के बीच 7: लोग स्वरोजगार में लगे हुए थे। श्रम बाजार से बाहर हुए युवा दर्शन नहीं बल्कि अपराध की ओर बढ़े थे।

कुछ लोगों को जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया जाता था 1996 में रूस के सम्पूर्ण श्रमबल के 15.8 लोगों को 40 कार्य दिवसों के लिए प्रशासनिक छुट्टी पर भेजा गया था। 43: श्रम बल को कुछ भी पैसा नहीं मिला। 6–7: को कम समय के लिए काम मिला। सभी कम समय के लिए काम करने वालों और प्रशासनिक अवकाश पर जाने वालों में से 2/3 उद्योग में थे। जिनमें से 16: उद्योग श्रमबल कम समय वाला था। और 37: प्रशासनिक अवकाश वाला अधिकारिक आँकड़े संकेत देते थे कि लघु समय व प्रशासनिक अवकाश वाले लोगों की संख्या में कमी आ रही था। 1998 के श्रमबल सर्वेक्षण के अनुसार श्रमबल के 34: या तो काम से बाहर थे या कम समय के लिए काम कर रहे थे। रोजगार के क्षेत्र से बाहर वे लोग जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा था और वे लोग जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा था वेतन राशि—जिसका भुगतान नहीं हुआ था। वह 1 जुलाई 1998 को 70 अरब नये रुबल के बराबर थी। यह राशि रूस के सभी रोजगार के एक महीने के वेतन के बराबर थी। बहुत से विश्लेषक वेतन व भुगतान में भारी शिरावट वेतन के भुगतान के महत्व को कम करके आँकते थे। उनका मत था कि बहुत से वे लोग जो बहुत कम वेतन या बिल्कुल वेतन नहीं पाते हुए प्रतीत होते थे वे अनिधिकारिक अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी आय प्राप्त कर रहे थे। परन्तु सच यह है कि एक अल्पसंख्यक वर्ग ही द्वितीय रोजगार में हाथ लगाता था उनमें से एक छोटा हिस्सा ही नियमित रूप से उसमें लगा रहता था और किसी तरह से वे घर को चला सकने में एक छोटा सा सहयोग पा लेते थे।

तस्वै सर्वेक्षण के आँकड़े द्वितीय रोजगार के बारे में विस्तृत जानकारी देते थे, इनके अनुसार 1994, 95, 96 में काम करने वाले लोगों में से 4: द्वितीय रोजगार भी कर रहे थे। इन तीन वर्षों में द्वितीय रोजगार जारी रखने वालों का अनुपात 5 में से 1 से भी कम था।

खुली बेरोजगारी की दर अभी भी बहुत ऊँची थी। श्रम बाजार की स्थिति ने गरीबी तथा आय की असमानता को बढ़ाया था। महिलाओं की भी दशा बहुत अच्छी नहीं रह गयी उनको जिस तरह की सुविधाएं सोवियत व्यवस्था में मिलती थीं वह बन्द हो गयी। रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में काफी कमी आई। रूस के एक श्रम मंत्री का बड़ा हास्यास्पद बयान कि जब पुरुषों को ही काम नहीं मिल पा रहा है तो स्त्रियों के बारे में क्या सोचना वहाँ की स्थिति का चित्रण कर देता है।

व्यापक पैमाने पर प्रतिभा-पलायन भी हुआ था। डाक्टरी व इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग वाणिज्यिक क्षेत्रों में जाने लगे थे क्योंकि उन क्षेत्रों में उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं रह गयी थी।

उपर्युक्त परिस्थितियों के चलते सामाजिक असमानता भी व्यापक पैमाने पर बढ़ी थी। उच्चतर बेरोजगारी और घटती आर्थिक सुरक्षा से जन्मा राजनीतिक कसमकस निजीकरण और पुनर्संरचना की गति को बड़े पैमाने पर बाधित कर रहा था और सुधार प्रक्रिया की गति को घटा भी रहा था। इसलिए समाजिक और आर्थिक पुनर्संरचना के उचित स्तर के बीच एक बारीक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता थी। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा को लागू किया जाना श्रेयस्कर होता क्योंकि यह बढ़ती बेरोजगारी की दशा में सामाजिक सहमति कायम करने में तथा पुरानी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था को तोड़ने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता था इसके अलावा संक्रमण प्रक्रिया में श्रम बाजार की अधिक सीधे तौर पर भूमिका थी। मानव पूँजी का पुनरावंटन, पुनर्वितरण सफल पुर्नसंरचना का एक मूलभूत पहलू था। यह सच है कि इन कुशलताओं और प्रतिभाओं के एक बड़े भाग का पुनरावंटन बाजार द्वारा ही किया गया। लेकिन श्रम बाजार नीतियाँ श्रम आपूर्ति एवं माँग दोनों के स्तर एवं संरचना में बड़े परिवर्तन के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। मानवीय हितों को जिस तरह से बाजार अर्थव्यवस्था व लाभ-हानि के सन्दर्भ में व्यापक तौर पर मजदूरों व श्रमिकों का शोषण करने के लिए खुली छूट प्रदान कर दी गयी। यह पूँजीवाद के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं था। लाभ का बड़ा हिस्सा कुछ विशेष लोगों तक सीमित रहना व व्यापक तबक्के की जीवन स्थितियों का निर्धारण करने की जो शक्ति बाजार अर्थव्यवस्था के माध्यम से प्राप्त की गयी थी, वह अपने दोषों को छिपा नहीं सकती उसे अपने वास्तविक रूप में प्रकट होना ही है बेरोजगारी की समस्या उसका एक मात्र प्रतीक थी जिसका समाधान सम्पूर्ण रूप से पूँजीवादी व्यवस्था में नहीं हूँडा जा सका था। रूस के पूँजीवादी पथ पर अग्रसर होने का अभी तक शुभ संकेत नहीं मिला। इस संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था ने लोगों को गरीबी रेखा के नीचे तक गिरा दिया था या बेरोजगार लोगों वाली अर्थव्यवस्था की तरफ ढकेल दिया था।

1. Anders, Aslund – How Russia Became a Market Economy, The Brookings Institution, Washington D.C. 1995.
2. L : Buszynski, Russian Foreign Policy After the Cold Ward, Praeger, Westport 1996.
3. Neil, Malcolm (ed.), Russia and Europe: An End to Confrontation, Printer, London 1994.
4. Vinay Kumar Malhotra – Gorbachevian Revolution in the Soviet Union ; Collapse or Renewal of Socialism, Anmol Pub. New Delhi 1991.
5. Yeal Tamir , Liberal Nationalism – Princeton University Princeton 1993.
6. David, Lane (ed) Russia in Transition : Politics Privatization and Inequality Longman Harlow (U.K.) 1995.
7. A. David Dyker , The Structural Origins of Russian Economic Crisis, Post Communist Economics Vol. 12 No. 1 March , 2000
8. Anuradha M. Chenoy – Systemic Change and Systemic Collapse, Seminar No. 343, May 1992, New Delhi.